संपादकीय

मानसून अभी समाप्त हुआ है किंतु मुझे विश्वास है कि जब वर्ष 1875 में भारतीय मौसम विभाग की शुरूआत हुई थी तो उससे यही उम्मीद की जाती थी की वह मौसम की सही–सही भविष्यवाणी करे न की मंगल ग्रह पर मंगलयान भेजे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ हम आज मंगलग्रह पर पहुंच चुके हैं लेकिन मौसम की सही भविष्यवाणी अभी तक नहीं कर पाते हैं।

सितम्बर में भारी वर्षा होने से वर्षा का जो 87 प्रतिशत भाग कम हुआ था वह पूरा हुआ आंकडों में तो नजर आता है लेकिन बुआई के समय बेमौसम बरसात होने से फसल को नुकसान होता है। फसल की बुआई का समय लेटिट्यूड पर सूरज की दिशा पर निर्भर करता है। जो वर्षा एक फसल और किसी एक क्षेत्र के लिऐ लाभकारी हो सकती है वही वर्षा अन्य फसलों या क्षेत्रों के लिऐ हानिकारक हो सकती है।

मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि लगभग सभी क्षेत्रों में वर्षा का प्रतिशत औसत से अच्छा रहा है जो कि आंकडों के हिसाब से तो अच्छा लगता है लेकिन फसल उगाने के लिऐ उपयोगी नहीं है। भारत में मानसून की भविष्यवाणी कभी सही नहीं होती और यह किसी विशेष क्षेत्र के लिऐ भी उपयोगी नहीं रह जाती जिसका उपयोग ब्लॉक स्तर पर होना चाहिऐ न कि जिला स्तर पर, इस प्रकार किसी भी किसान के लिऐ मौसमी भविष्यवाणी असंगत हो जाती है।

एक कारगर मौसम भविष्यवाणी के परार्मश का लाभ न केवल पूरे देश को मिलता है बल्कि किसानों को भी निर्णय लेने में सहायता देता है कि वे समय रहते हुऐ क्या करें और क्या न करें ताकि उन्हें हानि कम, उनका जोखिम न रहे तथा वे उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाऐं। इसका उपयोग फसल आधारित मौसम बीमा के लिऐ तो किया जा सकता है किंतु अधिकतम किसानों के लिऐ इसका उपयोग नहीं है।

उदाहरण के लिऐ इस वर्ष धान और बासमती उगाने वाले किसानों को हानि हुई है क्योंकि बिजली, डीजल महंगा होने और जलस्तर काफी नीचे जाने के कारण गहराई तक टयूबवैल लगाने में उनका खर्चा अधिक हुआ। बद से बदतर यह हुआ कि धान के मूल्य पिछले वर्ष से काफी कम हैं।

धान और चावल जैसी गैर विनाशशील जिंसों के मूल्य ही नहीं, बल्कि कपास, सरसों, मक्का, सोयाबीन, मसूर, चना, गेहूं भी खुले बाजार में पिछले वर्ष के मूल्यों की तुलना में 25 प्रतिशत से कम मूल्य पर बिक रहे हैं। अंतराष्ट्रीय बाजार में भी कृषि जिंसों के भाव मंदे हैं और आशंका है कि कुछ समय और ये मंदे ही रहेंगे। ये जिंसें विनाशशील नहीं हैं किंतु इन जिंसों के मूल्य तेजी से नीचे गिरने के कारण किसानों के लिऐ अच्छे दिन का सपना टूट रहा है।

किसानों के अथक प्रयास से भारत ने खाद्य उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ताकि खाद्य मुद्रास्फीती पर नियंत्रण रखा जा सके। वर्षा के कारण होने वाली हानी से प्रभावित किसानों के संकट को दूर करने के लिऐ सरकार को प्रभावित किसानों के लिऐ बोनस की घोषणा करनी चाहिऐ।

श्री सुरेश प्रभु, पूर्व केंद्रीय मंत्री

यहां हम ऐसे विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं जो हमें प्रत्येक दिन प्रभावित करता है। खाद्य मुद्रास्फीति के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं है। जिन लोगों की आय सदा एक जैसी नहीं रहती और जिन लोगों को भत्ते आदि मिलते रहते हैं उनका जीवन स्तर फिर भी अच्छा है। भारत के लिऐ बाह्य स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती मुद्रास्फीति की है जिस कारण भारत का केन्द्रीय बैंक ब्याज दरें कम नहीं कर पा रहा है। आर्थिक वृद्धि में ब्याज की दरों का महत्वपूर्ण भाग होता है। लोग निवेश उसी आधार पर करते हैं जिस दर पर वे पूंजी उधार लेते हैं, जब मुद्रास्फीति अधिक होगी तो ब्याज दरें भी उंची होंगी और इस कारण आर्थिक वृद्धि कम होगी।

मुद्रास्फीति की रूपरेखा : खाद्य मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर है किंतु इसे समान नहीं बनाया जा सकता क्योंकि भिन्न–भिन्न जीवनस्तर रखने वाले लोग अलग–अलग खाद्य वस्तुओं का उपभोग करते हैं। संपूर्ण फूड़ बास्केट में क्या अनाज से मुद्रास्फीति अधिक हो रही है।

कुछ सुझाव : खाद्य उत्पादन बढ़ाना लेकिन कैसे। उन जिंसों का उपत्पादन बढ़ाया जाऐ जिनकी कमी है। कई मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र अनोखा क्षेत्र है जिसमें कई चुनौतियां हैं। जल का मुद्दा सबसे बढ़ा मुद्दा है। 85 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में पानी का उपयोग किया जाता है। इसलिऐ जल की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। हमें इस बात पर विचार करना है कि पानी का कम उपयोग करके कृषि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाऐ। किंतु, यह एक चुनौती रहेगी। हमें सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने की आवश्यकता है, यह वृद्धि 9 प्रतिशत से उपर होनी चाहिऐ। इसके लिऐ निर्माण क्षेत्र को बढ़ाना होगा और निर्माण क्षेत्र के लिऐ भी बहुत अधिक पानी की आवश्यकता है। सर्विस सैक्टर, जिसका अर्थव्यवस्था में 60 प्रतिशत अंशदान है, उसे भी पानी की आवश्यकता है। अतः कृषि को तो पहले की तरह पानी की आवश्यकता रहेगी लेकिन अन्य क्षेत्रों को भी पानी की आवश्यकता है। इस कारण पानी की कमी तो रहेगी, किंतु हो सकता है कृषि क्षेत्र फले–फूले लेकिन अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और दुबारा मुद्रास्फीति की समस्या आऐगी क्योंकि खरीद शक्ति कम होती जाऐगी। अतः इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पानी के मुख्य मुद्दे पर विशेष प्रकार से ध्यान देना होगा। विश्व में 4 प्रतिशत जल ही उपलब्ध है और जल का स्तर नीचे जाने के कारण इसे निकालने के लिऐ बिजली की अधिक आवश्यकता होगी। अंडरग्राउंड जल का अधिक उपयोग करने के कारण कई अन्य समस्याओं के साथ–साथ खाद्य सुरक्षा की समस्या भी आऐगी।

भूमि : विश्व में भूमि का भाग 2.2 प्रतिशत है। भूमि की कभी समस्या नहीं रही लेकिन भूमि की उर्वरता की समस्या है क्योंकि यूरिया पर सब्सिडी देने के कारण भूमि की उर्वरता नष्ट हो रही है तथा पौटेशियम या फॉस्फोरस उर्वरकों पर सब्सिडी नहीं दी जाती। इस प्रकार एनपीके का अनुपात गिर रहा है और अनुपात कम होता जा रहा है जिस कारण भारत की खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती जाऐगी। अतः उन नीतियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जो उच्च स्तर की भूमि से संबंधित हैं। अतः उर्वरक की नीति महत्वपूर्ण है। उर्वरकों का उपयोग पूरे ध्यान से करना चाहिऐ। अभी तक उर्वरकों पर सब्सिडी केवल उद्योगों को ही दी जाती है और यह सब्सिडी सीधे किसानों को दी जानी चाहिऐ। लेकिन उर्वरकों की खरीद भी एक मुद्दा होगी जिसमें किसानों को वित्तीय बाधाऐं आऐंगी इस कारण बैंकों का समानीकरण करना चाहिऐ जिससे किसानों को सीधे ही आर्थिक सहायता मिल सके। कृषि क्षेत्र पर बहुत से बाह्य तत्वों का प्रभाव होता है, इस कारण इन्हें नहीं छोडा जा सकता। इन सभी मुद्दों पर इकट्ठे ध्यान देने की आवश्यकता है। जल, भूमि और उर्वरकों जैसे प्रत्येक विषय में सुधार करना होगा। चीन ने वर्ष 1978 में कृषि सुधार आरंभ किऐ लेकिन वहां अधिकतम भूमि सरकार के पास है। किसान जमीन पट्टे पर लेकर खेती करते हैं। लेकिन भारत में अधिकतम जमीन निजी लोगों के हाथों में है। चीन में सरकारी स्वामित्व होने के कारण, वे कई परिवर्तन कर देते हैं और उत्पादन बढा रहे हैं तथा भारत की तुलना में उत्पादन 2 गुणा कर चुके हैं जबकि उनके पास भी भारत जितना ही कृषि क्षेत्र है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। इस कारण हमें विभिन्न प्रकार के सुधार करने होंगे जिसमें तकनीकी के उपयोग से कृषि उत्पादन बढा ना होगा।

यदि हम खाद्य मुद्रास्फीति की पृष्टभूमि में जाऐं तो हमें पता चलेगा की कई क्षेत्रो में सुधार की आवश्यकता है जिनसे कृषि क्षेत्र में अवश्य सुधार होगा। खाद्य मुद्रास्फीति में परिवर्तन की शुरूआत की जा सकती है और इससे कई क्षेत्रों में विकास भी होगा।

विभिन्न कार्यक्रमों के कारण किसानों की आय बढ़ी है इस कारण मुद्रास्फीति मांग पर निर्भर होती है और मांग से संबंधित मुद्रास्फीति एक अच्छी आशा है लेकिन हमें मांग में कमी कराने का प्रयास नहीं करना चाहिऐ और आपूर्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शीत भंडारण की संख्या बढाने की आवश्यकता है। ऐसे मुद्दों पर तुरंत कार्यवाही की जाऐ और इनका तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है।

हम आशा करते हैं कि किसानों की आय इतनी बढ़ जाऐ कि वह इस आय को अपनी खेती में लगाऐं और आर्थिक कार्य के रूप में उभरे। कृषि क्षेत्र अब ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जहां पर पूंजी निवेश करके इससे लाभ अर्जित किया जा सके। उत्पादन बढ़ाने के लिऐ बिजली महत्वपूर्ण है, लेकिन जमीन से अधिक पानी निकालना भी अच्छा नहीं रहेगा। इस प्रकार की नीतियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

<u>प्रोफेसर अरूण कुमार, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, जेएनयू</u>

खाद्य मुद्रास्फीति के विषय में कई विवाद हैं जिनका निपटान करने की आवश्यकता है। मुझे यह उदाहरण देने का बहुत शौक है कि '1 हाथी और 7 अंधे आदमी'। यदि मैं हाथी की टांग को छुउंगा तो मैं सोचुंगा की यह बिल्डिंग का पिलर है और यदि मैं उसकी पूंछ छुअंगा तो सोचुंगा की यह झाडू है। इस प्रकार मैं हाथी की समस्या दूर नहीं कर रहा हूँ बल्कि बिल्डिंग या झाडू की समस्या या होजपाईप की समस्या दूर करूंगा। यही मुद्रास्फीति पर हो रहा है, विभिन्न लोगों के विभिन्न विचार हैं, क्योंकि कई प्रकार के सोचने वाले लोग या संस्थाऐं हैं जो अलग–अलग विषयों पर बहस करते हैं और अलग सुझाव देते हैं। इस कारण से हर कोई यही कहता है कि मुद्रास्फीति को दूर करने के कई समाधान हैं। कोई तो कहेगा मंडियों का समाधान, कोई कहेगा सरकारी नीति से समाधान होगा इत्यादि। मैं आर्थिक पहलुओं के बाह्य तत्वों का उल्लेख करना चाहता हूँ जिनसे मुद्रास्फीति पर सीधा प्रभाव पड़ता है जैसे आपको विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न आर्थिक नीतियों को आपस में मिलाना होगा, जिसमें पब्लिक का पैसा और अन्य वस्तुऐं शामिल हैं, भारत में मुद्रास्फीति की प्रकृति को समझने से पहले इन पर विचार करना होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पिछले कई वर्षों से कृषि क्षेत्र को हाशिऐ पर रखा गया है। स्वतंत्रता के समय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का लगभग 55 प्रतिशत योगदान था और आज यह कम होकर लगभग 14 प्रतिशत रह गया है। इस कारण नीति निर्माण में यह हाशिऐ पर ही रहा और अन्य प्रकार से भी इसे महत्व नहीं दिया गया।

एक अन्य महप्वपूर्ण विषय है कि कृषि में एक ही प्रकार के लोग नहीं हैं, इसमें किसानों के विभिन्न वर्ग हैं और उनके अलग–अलग हित हैं। जैसे की अमीर किसानों के अलग हित और सोच है और मजौले व छोटे किसानों के अलग हित। इस कारण इन सभी पहलुओं को नीतियों में स्थान देना चाहिए क्योंकि नीति में इन सब पर विचार नहीं किया जाता जिससे एक वर्ग या अन्य वर्ग इस निर्माण में शिकायत करता रहेगा। अतः चालू मुद्रास्फीति के कुछ आंकड़ों पर अन्य वक्ता भी बोलेंगे जैसे डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति काफी उंची है और सीपीआई मुद्रास्फीति भी उंची है तथा इसमें कृषि का व्यापक अंशदान है जिसके लिऐ मैं आशा करता हूं कि अन्य वक्ता भी इस पर घ्यान देंगे।

तीन मूल्य ऐसे हैं जो कृषि से संबंधित हैं जैसे थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और खेतो पर फसल मूल्य। किसान को खेत का मूल्य मिलता है, उपभोक्ता तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर भुगतान करता है और खेत के मूल्य और उपभोक्ता के मूल्य के बीच बहुत बडा अंतर होता है, इस कारण किसान और उपभोक्ता दोनों ही मुद्रास्फीति की शिकायत करते हैं क्योंकि एक को कम मूल्य मिलता है दूसरे को अधिक भुगतान करना पड़ता है। अब यह स्पष्ट है कि लोगों के विभिन्न वर्ग, जैसे कृषि मजदूर या फैक्ट्री मजदूर अथवा व्हाईट कॉलर मजदूर या अमीर। वे अलग–अलग खाद्य वस्तुओं का उपभोग करते हैं इस कारण विभिन्न लोगों पर मुद्रा स्फीति का विभिन्न प्रभाव पड़ता

है जैसा परंजॉय कहते हैं। अमीरों पर तो खाद्य मुद्रास्फीति का प्रभाव अधिक नहीं पड़ता लेकिन गरीब आदमी का तो कुल खर्च का अनाज पर 50 प्रतिशत खर्च होता है उन्हें अधिक नुकसान होता है। मुद्रास्फीति के विषय या क्षेत्र अर्प्याप्त हैं क्योंकि थोक सूचकांक में सेवा का घटक नहीं होता जबकि सेवा क्षेत्र में 60 प्रतिशत से अधिक उपभोग किया जा रहा है जैसा उत्पादन के क्षेत्र में होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी सेवाओं को केवल 16 प्रतिशत आंका गया है, इसलिऐ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति के मूल्य पूरी तरह नहीं आ पाते जिस पर औसत दर्जे के लोग गलियों में असंतोष प्रकट करते हैं और इस प्रकार सरकार कहती है कि मुद्रास्फीति की दर स्थिर हो रही है लेकिन जनता जानती है कि यह दर बहुत उंची है क्योंकि हाल ही में सेवा मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है और जैसा सरकार घोषित करती है वास्तव में मुद्रास्फीति की दर वह नहीं होती।

सरकार भवन सूचकांक बनाकर सेवा क्षेत्र को इसमें मिलाने का प्रयास कर रही है किंतु इस पर कार्य अभी चल रहा है। मैं सावधान करना चाहता हूँ कि अनाज, उत्पादन से संबंधित नहीं है बल्कि इस पर रोजगार और जीवन शैली निर्भर करती है। अतः खाद्य मुद्रास्फीति पर विशेष प्रकार से ध्यान देने आवश्यकता है। यह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने का प्रश्न नहीं है, हम आयात करते हैं। रोजगार, जीवनशैली और जहां तक कि यदि भूमिअधिग्रहण किया जाऐ तो भी आयात प्रभावित करता है। इस कारण खाद्य सुरक्षा अतिमहत्वपूर्ण है। वर्ष 1966–67 में सूखा पड़ने के बाद इंदिरा गांधी के समय में खाद्य सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिऐ वर्ष 1967 में डीवैल्यूऐशन करना समय की पुकार थी, हमें बहुत अधिक डीवैल्यूऐशन करने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त 40 प्रतिशत बच्चे और महिलाऐं कुपोषण के शिकार है जिससे वे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और इस प्रकार के वर्ग के लोगों के हित के लिऐ अनाज बहुत महत्वपूर्ण है। अतः अनाज नियंत्रण और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिऐ बनाई जा रही नीतियों में खाद्य सुरक्षा बिल पर विशेष ध्यान देना होगा।

मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले पहलू : मुद्रास्फीति पर मांग और आपूर्ति का विशेष प्रभाव पडता है जैसा निर्माण क्षेत्र में नहीं होता क्योंकि वहां नियत बाजार मूल्य होते हैं किंतु कृषि मंडियों में मूल्यों में उतार चढाव मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। देश में लगभग 540 मंडियां हैं लेकिन एक भी मंडी में किसी का एकाधिकार नहीं है इस कारण वहां पर निर्माण क्षेत्र के समान मूल्य नियत नहीं किऐ जा सकते जिसका कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के बीच के कारोबार की शर्तों पर पूरा प्रभाव पड़ता है। अभी भी कृषि मूल्यों में उतार चढ़ाव वर्षा पर निर्भर है क्योंकि आधे क्षेत्र पर ही सिंचाई हो पाती है। इस कारण अनाज के मूल्यों में अत्यधिक उतार चढाव आता है। सिंचाई और परिवहन दोनों क्षेत्रों में प्राईवेट और पब्लिक निवेश बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यद्यपि कृषि क्षेत्र पर 50 प्रतिशत जनसंख्या निर्भर है इसमें कुल निवेश का केवल 7–8 प्रतिशत भाग है जबकि दूसरी तरफ संगठित क्षेत्र में निवेश का लगभग 80 प्रतिशत भाग है जबकि वहां पर रोजगार का प्रतिशत केवल 6.5 है। इस प्रकार संगठित और कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा असमानता है इसी के परिणामस्वरूप आय में असमानता होती है।

अलग–अलग सोच है कि कृषि के कारोबार में बहुत ज्यादा लाभ है, उत्पादन कम होने पर जिंसें महंगी बिकती हैं, काला धन बाहर आता है लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक का इस पर कोई नियंत्रण नहीं और जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा धन है वह संगठित क्षेत्र है और इस प्रकार के व्यापारी जमाखोरी करते हैं जब माल की कमी होती है और उंचे भाव पर माल की बिक्री कर देते हैं।

माल रखने की सरकारी नीतियां : हमारे पास बफरस्टॉक रखने की मांग 27 मिलियन टन है लेकिन हम 80 मिलियन टन बफरस्टॉक रखते हैं जिसमें से 10–15 मिलियन टन सड़ या नष्ट हो जाता है। 1960 के दशक से न्यूनतम समर्थन मूल्य, एफआरपी और खरीद तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरूआत की गई क्योंकि मूल्यों में बहुत उतार चढाव था इसलिऐ मूल्यों की दोहरी रणनीति बनाई गई और न्यूनतम समर्थन मूल्य एवम जारी मूल्य तथा बाजार मूल्य नियत किऐ जाते थे। इससे गरीब लोगों के उपभोग की मांग को पूरा करने में सहायता मिली लेकिन जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचता था तो इससे मूल्य स्थिर रहे और कम उत्पादन होने वाले वर्षों में भी जब मूल्य तेजी से बढ़ते थे और गरीब लोग प्रभावित होते थे तो भी मूल्यों को स्थिर रखकर समानता लाई जाती थी जबकि

अच्छी फसल होने के वर्षों में जब मूल्य बहुत नीचे जाने होते थे तो खरीद मूल्य नियत करके इन्हें बहुत नीचे नहीं जाने दिया जाता था और आपूर्ति स्थिर रखी जाती थी। इस प्रकार आपूर्ति और मांग दोनों के लिऐ 1960 के दशक के मध्य में दोहरी मूल्य नीति बनाकर गरीबों की मांग और आपूर्ति पर नियंत्रण करने में सहायता मिली थी। अब खुला बाजार करने के कारण विश्व व्यापार संगठन तथा आयात से खाद्य उत्पादन और इसके मूल्यों पर विचारणीय प्रभाव पड रहा है। फसल लगाने की भी व्यापक पद्धितयां हैं जहां पर फूलों की खेती, बागवानी वस्तुओं तथा इस प्रकार के उत्पादनों का खाद्य उत्पादन से अधिक भाग है जबकि इनका कम मात्रा में उपयोग किया जाता है लेकिन इसी से कृषि की पद्धति निर्धारित हो रही है, लेकिन अधिकतम लोगों की मांग और इसे निर्यात से पूरा करना, इस लागत से मुद्रास्फीति पर प्रभाव पडता है। यह तो केवल कुछ चुनी हुई फसलों का एमआरपी और एमएसपी तथा एफआरपी है, हम देख सकते हैं कि वर्ष 2013–14 और वर्ष 2009–10 की अवधि में इनमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई इनका भी मुद्रास्फीति पर प्रभाव पडा है। अब कुछ बाह्य आर्थिक पहलुओं से भी कुल मांग बढ़ रही है क्योंकि वर्ष 2003–04 के पश्चात सकल घरेलू उत्पाद भी तेजी से बढ रहा है। यद्यपि अब हम लगभग 5 प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं लेकिन यह भी काफी अधिक है जिससे मांग में वृद्धि हो रही है और यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा की आय का वितरण अच्छी जीवनशैली के लोगों के पक्ष में जा रहा है जिस कारण विभिन्न प्रकार की फसलों की मांग बढती है और इनका मूल्यों पर प्रभाव पडता है। वित्त नीतियों का सभी मूल्यों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है जैसे आर्थिक सहायता की भूमिका, अप्रत्यक्ष करों की भूमिका जिनपर हमें अनिवार्य ध्यान देना चाहिऐ ताकि हम समझ सकें मुद्रास्फीति किस प्रकार की है और किन क्षेत्रों में बढ़ रही है। उपकरणों की बढ़ती लागत भी प्रभाव डालती है जैसे पैट्रोल के उत्पाद, जिनका परिवहन की लागत पर उर्वरक और अन्य उपकरणों की लागत पर भी प्रभाव पड़ता है। इन बढ़ते हुऐ मूल्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जैसा सभी समाचारपत्रों में उल्लेख किया जाता है। खेती के बाहर भी रोजगार मिलने से वेतन पर प्रभाव पडता है जिस प्रकार मनरेगा के द्वारा रोजगार दिया जा रहा है जबकि कुछ लोगों को संदेह है कि इसका वेतन पर अधिक प्रभाव पड़ता होगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि वेतन बढ रहे हैं जिनसे लागत में वृद्धि होने पर प्रभाव पड़ता है। पिछले 3–4 वर्षों में रूपये की कीमत बहुत गिर चुकी है। 1 डॉलर की कीमत 44 रू. से बढकर 68 रू. हो गई थी, अब यह लगभग 60–61 रू. पर स्थिर है जिसका आयात मुद्रास्फीति पर प्रभाव पढता है और आखिर में इसका प्रभाव खाद्य मुद्रास्फीति और अन्य क्षेत्रों पर, विशेषकर पैट्रोल के उत्पादों पर प्रभाव पडता है। वायदा कारोबार और वित्तीय बाजारों में पैसा निवेश किया जा रहा है जिसका प्रभाव कृषि पर पडा है और काफी हद तक पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसका प्रमुख कारण वायदा कारोबार में अधिक निवेश किया जाता है जो कृषि उत्पादों पर सीधे प्रभाव डालते हैं।

काले धन से मुद्रास्फीति का गहरा रिश्ता है क्योंकि इस माध्यम से काली कमाई की जाती है जो लागत से अधिक होती है तथा पूरी अर्थव्यवस्था में लागत में वृद्धि हो जाती है। राजस्व अर्जित करने की सीमा है किंतु लागत की कोई सीमा नहीं इस प्रकार काले धन का लागत पर भी और मांग पर भी ठोस प्रभाव पडता है। काला धन लगाने वालों और सेवा क्षेत्रों में पैसा लगाने वाले लोगों का प्रतिशत केवल 3 है। इस प्रकार कृषि और सेवा क्षेत्र के बीच असमानता बढ़ रही है यदि काले धन को शामिल कर लिया जाऐ। यदि आप ज्ञात स्रोत्रों के धन की गणना करें तो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का भाग केवल 6 प्रतिशत, जबकि ज्ञात स्रेत्रों की आय का भाग सकल घरेलू उत्पाद में 14 प्रतिशत है। अतः इसका मांग और मुद्रास्फीति की प्रकृति तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता ही है। यदि बलैक और व्हाईट इकानॉमी को इकट्ठा मिलाऐं तो उच्चतम अनुपात 3 प्रतिशत और नीचे का 40 प्रतिशत होता है, यह बढकर 1:60 हो जाता है। जबकि यदि केवल व्हाईट की गणना करें तो यह केवल 1:12 है। इस प्रकार मांग के अधिकतम भाग में काला धन है। आपूर्ति क्षेत्र से एक अन्य प्रभाव यह पड़ता है कि वायदा कारोबार करने के लिऐ काला धन मिल जाता है। इस प्रकार वायदा या सट्टा बाजार की मात्रा बढ़ती है जबकि व्हाईट इकनॉमी का भाग नहीं बढ़ पाता और इस काले धन का खाद्य मूल्यों पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। व्हाईट इकनॉमी और कृषि में, शहरी क्षेत्रों और राजधानियों में निवेश नहीं किया जाता है।

हमारा अनुमान है कि अभी हम विश्व में कर (टेक्स) बचाने का अध्ययन कर रहे हैं और भारत से पैसा बाहर न जाऐ लेकिन अनुमानित 1.2 ट्रिलियन डॉलर पिछले 60 वर्षों में बाहर जा चुके हैं। यही पैसा भारतीय अर्थवयव्स्था में लगाया

जा सकता था, इसे यहां न लगाकर विदेशों में लगाने से हमारी अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी आई जिसका कृषि उत्पादन और इसकी वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है। मुद्रास्फीति, विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिऐ मैं कुछ उपाय सुझाना चाहता हूँ : काले धन की विचारणीय भूमिका है। इस पर रोक लगनी चाहिऐ जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर नीचे आंऐगी। प्रशासनीक कदम उठाकर सट्टेबाजी को रोका जाऐ और हाल ही में हमने देखा है कि सूखा पड़ने की आशंका के बाद भी पिछले कुछ महीनों में जिंसों के भाव बहुत ज्यादा नहीं बढ़े क्योंकि वायदा कारोबार या सट्टेबाजी को रोकने के लिऐ प्रशासनीक कदम उठाऐ गऐ थे। मूल्य वृद्धि, विशेषकर खाद्य वस्तुओं के मूल्यों पर रोक लगाने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः इस सिस्टम को बढाना चाहिऐ। पीडीएस के स्थान पर नकद भुगतान करना अच्छी रणनीति नहीं होगी क्योंकि ऐसा होने पर हम यह सुनिश्चित नहीं कर पाऐंगे कि दिया गया पैसा अनाज खरीदने के लिऐ या कुछ और खरीदने के लिऐ उपयोग किया गया है। आपूर्ति में सुधार करने के लिऐ शीत भंडारों और परिवहन व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि जिंसें या उत्पादन सड़कर नष्ट न हो। घोषित जन धन योजना के स्थान पर छोटे और मझौले किसानों को ऋण दिया जाना चाहिऐ क्योंकि जन धन योजना उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। कृषि में अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जाऐ और यह कृषि वस्तुओं के लिऐ भी उपयोग किया जाना चाहिऐ। खाद्य सुरक्षा के विषय में कोताही न बरती जाऐ और अनाज के अधिकार की नीति को क्रियान्वित किया जाना चाहिऐ।